

ज़िला नरिवाचन प्रबंधन योजना

स्रोत: द हट्टि

आगामी लोकसभा चुनावों के मद्देनजर, चुनावों का संचालन तेज़ी से जटिल व बहुआयामी हो गया है, जिससे स्वतंत्र, नष्पिक्ष एवं समावेशी चुनावी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिये सावधानीपूर्वक योजना और कार्यान्वयन की आवश्यकता होती है।

- इस योजना प्रक्रिया की आधारशिला ज़िला नरिवाचन प्रबंधन योजना (District Election Management Plan - DEMP) है।

ज़िला नरिवाचन प्रबंधन योजना (DEMP) क्या है?

- **परिचय:**
 - **DEMP** एक व्यापक दस्तावेज़ है जो ज़िलों में चुनावों के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिये आँकड़ों और विश्लेषण का उपयोग करता है।
- **तैयारी/रणनीति:**
 - **भारत नरिवाचन आयोग** के नरिदेशों के अनुसार, **DEMP** को मतदान की संभावित तारीख से कम से कम छह माह पहले तैयार किया जाना चाहिये।
 - चुनावी प्रक्रिया की गतिशीलता के लिये अक्सर चुनावों की आधिकारिक घोषणा के बाद समय-समय पर पुनर्मूल्यांकन और योजना में संशोधन की आवश्यकता होती है।
 - DEMP के प्रभावी कार्यान्वयन में **चुनावी अधिकारियों, प्रशासनिक नकियाँ, कानून प्रवर्तन एजेंसियों** और अन्य प्रासंगिक हतिधारकों को शामिल करते हुए एक समन्वित प्रयास शामिल है।
 - राजनीतिक संस्थाओं और मीडिया आउटलेट्स के साथ नरिधारित कार्यक्रमलाप की भी व्यवस्था की जाती है ताकि उन्हें चुनावी नयियों एवं प्रक्रियाओं पर व्यापक जानकारी प्रदान की जा सके।

DEMP के तत्त्व क्या हैं?

- **ज़िला प्रोफाइल:**
 - यह नरिवाचन रणनीति का मूलभूत तत्त्व है, जिसमें नरिवाचन क्षेत्रों का च्तिरण करने वाला एक राजनीतिक मानचित्र, प्रासंगिक **जनसांख्यिकीय एवं बुनियादी ढाँचे** के आँकड़े और ज़िले की प्रशासनिक संरचना एवं सामाजिक-आर्थिक विशेषताओं का अवलोकन शामिल है।
- **मतदान केंद्र अवसंरचना:**
 - मतदान केंद्रों की उपलब्धता और पहुँच बढ़ाने, रैंप, बजिली, प्रकाश व्यवस्था, पेयजल, शौचालय एवं इंटरनेट कनेक्टिविटी जैसी आवश्यक सुविधाएँ सुनिश्चित करने के लिये वसित रणनीतियाँ तैयार की गई हैं।
 - वकिलांग मतदाताओं और वरषिठ नागरिकों के लिये विशेष प्रावधान किये गए हैं, जिनमें सहायता डेस्क की स्थापना, 24/7 नयित्रण कक्ष, घरेलू मतदान वकिल्प एवं आवश्यक सेवा कर्मियों के लिये उन्नत डाक मतपत्र मतदान शामिल हैं।
- **EVM प्रबंधन:**
 - **इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM)** प्रबंधन नरिवाचन प्रक्रिया की अखंडता को बनाए रखने के लिये महत्त्वपूर्ण है, जिसमें EVM और **मतदाता सत्यापन योग्य पेपर ऑडिट ट्रेल (VVPAT)** के सुरक्षित भंडारण एवं उपलब्धता के लिये आवश्यक योजनाएँ शामिल हैं, जिसमें उनके परविहन एवं रखरखाव की योजनाएँ भी शामिल हैं।
- **व्यवस्थित मतदाता शक्ति और चुनावी भागीदारी (SVEEP) योजना:**
 - यह कम या उल्लेखनीय रूप से न्यूनतम भागीदारी दर वाले मतदान केंद्रों की पहचान करने के लिये मतदान डेटा का विश्लेषण करके चुनावी भागीदारी बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करता है।
 - इसमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का लाभ उठाना, वविधि समुदाय एवं युवा संगठनों के साथ जुड़ना और मतदान के दनि तक जागरुकता बढ़ाने वाले कार्यक्रम आयोजित करना शामिल है।
- **कार्मिक योजना और प्रशिक्षण:**
 - DEMP चुनाव कर्मियों की भरती, प्रशिक्षण, कल्याण और तैनाती के लिये एक व्यापक रणनीतिकी रूपरेखा तैयार करता है।
 - यह चुनाव कर्मियों का एक मज़बूत डेटाबेस स्थापित करने, उन्हें केंडर और समूह के आधार पर वर्गीकृत करने तथा वभिन्न चुनावी भूमिकाओं

में कर्मियों के अंतर को कम करने के लिये रणनीतिक रूप से उनकी तैनाती संबंधी आवश्यकताओं का आकलन करने की आवश्यकता पर ज़ोर देता है।

- योजना में **आदर्श आचार संहिता (MCC)** को लागू करने के लिये ज़िला-स्तरीय टीमों के लिये प्रशिक्षण कार्यक्रम शामिल हैं और सभी चुनाव कर्मियों हेतु व्यापक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनके पास संबंधित भूमिकाओं के लिये अपेक्षित कौशल एवं ज्ञान है।





भारत निर्वाचन आयोग



Drishti IAS



परिचय

- स्वायत्त संवैधानिक निकाय
- लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव का संचालन
- स्थापना- 25 जनवरी, 1950 (राष्ट्रीय मतदाता दिवस)

संवैधानिक प्रावधान

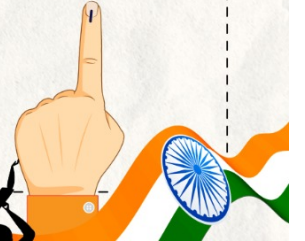
भाग XV-अनुच्छेद 324 से 329

संरचना

- 1 मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 चुनाव आयुक्त (राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त)
- **कार्यकाल** - 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो
- **सेवानिवृत्त चुनाव आयुक्त**- सरकार द्वारा पुनर्नियुक्ति के लिये पात्र
- **मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाना**- सदन की कुल संख्या के 50% से अधिक के समर्थन से उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों के बहुमत के साथ सिद्ध कदाचार या अक्षमता के आधार पर प्रस्ताव

प्रमुख भूमिकाएँ और जिम्मेदारियाँ

- चुनावी निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण
- मतदाता सूची तैयार करना और उसका पुनरीक्षण करना
- चुनाव कार्यक्रम और तारीखों को अधिसूचित करना
- राजनीतिक दलों को पंजीकृत करना और उन्हें राष्ट्रीय या राज्य दलों का दर्जा देना
- राजनीतिक दलों के लिये "आदर्श आचार संहिता" जारी करना



//

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

प्रश्न. नमिनलखिति कथनों पर वचिार कीजयि: (2012)

1. संघ राज्यक्षेत्रों का राज्यसभा में प्रतनिधित्व नहीं होता है ।
2. नरिवाचन झगड़ों का नरिणय करना मुख्य नरिवाचन आयुक्त के अधिकार क्षेत्र में है ।
3. भारत के संवधान के अनुसार, संसद में केवल लोकसभा और राज्यसभा होती हैं ।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 1 और 3
- (d) कोई भी नहीं

उत्तर: (d)

प्रश्न. संवधान (73वाँ संशोधन) अधनियिम, 1992, जसिका उद्देश्य देश में पंचायती राज संस्थाओं को बढावा देना है, नमिनलखिति में से कसिका प्रावधान करता है? (2011)

1. ज़िला योजना समितियों का गठन ।
2. राज्य चुनाव आयोग सभी पंचायत चुनाव कराएँगे ।
3. राज्य वतित आयोगों की स्थापना ।

नीचे दयि गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनयि:

- (a) केवल 1
- (b) केवल 1 और 2
- (c) केवल 2 और 3
- (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (c)

प्रश्न. नमिनलखिति कथनों पर वचिार कीजयि: (2017)

1. भारत का चुनाव आयोग पाँच सदस्यीय नकियाय है ।
2. केंद्रीय गृह मंत्रालय आम चुनाव और उपचुनाव दोनों के संचालन के लयि चुनाव कार्यक्रम तय करता है ।
3. चुनाव आयोग मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के वभिजन/वलिय से संबंधित वविादों का समाधान करता है ।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 2
- (c) केवल 2 और 3
- (d) केवल 3

उत्तर: (d)